



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02042025-262198
CG-DL-E-02042025-262198

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 104]

नई दिल्ली, रविवार, मार्च 30, 2025/चैत्र 9, 1947

No. 104]

NEW DELHI, SUNDAY, MARCH 30, 2025/CHAITRA 9, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

जांच शुरुआत अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मार्च, 2025

मामला सं. – एडी (ओआई) - 07/2025

विषय : यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस और थाइलैंड से "1500 सीरिज के इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबड़" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत

फा. सं. 6/07/2025 – डीजीटीआर.— समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित तत्संबंधी सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे इसके बाद 'नियमावली अथवा पाटनरोधी नियम' के रूप में भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके बाद "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) ने यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस और थाइलैंड ("संबद्ध देश") से "इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडाइन रबड़" (जिसे इसके बाद "संबद्ध वस्तु")

अथवा “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “ईएसबीआर” के रूप में भी कहा गया है) के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके बाद “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दाखिल किया है।

2. आवेदक ने यह आरोप लगाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तुओं के पाटित किए गए आयातों के कारण वास्तविक क्षति होने और वास्तविक क्षति होने की आशंका उत्पन्न हो रही है और उसने संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया है।

क. विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद 1500 सीरिज का इमल्शन स्टाइरीन ब्यूटाडीन रबड़ है, जिसे संक्षिप्त में ईएसबीआर -1500 के रूप में कहा जाता है।
4. एसबीआर को अनेक ग्रेड में उत्पादित किया जाता है, जिन्हें कोपोलिमर (स्टाइरीन का %), इमल्सीफायर टाइप, नोमिनल मूनी विस्कोसिटी, कोगुलेशन, विशिष्ट ग्रेविटी और उत्पाद स्टेन के स्तर से पहचाना जाता है। उन्हें 1000, 1500, 1600, 1700, 1800 और 1900 सीरिज में विभाजित किया गया है। विचाराधीन उत्पाद केवल ईएसबीआर 1500 सीरिज है।
5. संबद्ध वस्तुओं का उपयोग मुख्य रूप से टायरों के विनिर्माण के लिए किया जाता है क्योंकि इसमें अच्छा घर्षण प्रतिरोध होता है और एडिटिव द्वारा संरक्षित होने पर अच्छी एजिंग स्टेबिलिटी रहती है। इसका उपयोग कन्वेयर बेल्ट, शू सोल, वी-बेल्ट, मोल्डेड रबड़ वस्तुओं आदि में भी किया जाता है। प्राकृतिक रबड़ की तुलना में, ईएसबीआर में बेहतर प्रक्रिया क्षमता, समरूपता, हीट एजिंग और घर्षण प्रतिरोधकता होती है।
6. विचाराधीन उत्पाद को टैरिफ कोड 4002 19 के अंतर्गत अध्याय 40 के तहत वर्गीकृत किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।
7. आवेदक द्वारा किसी पीसीएन पद्धति का प्रस्ताव नहीं किया गया है। तथापि संबद्ध जांच में हितबद्ध पक्षकार इस जांच की शुरुआत की तारीख से 15 दिनों के भीतर विचाराधीन उत्पाद/ पीसीएन पद्धति, यदि कोई हो, पर अपनी टिप्पणियां प्रदान कर सकते हैं।

ख. समान वस्तु

8. आवेदक ने यह अनुरोध किया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से निर्यात किए गए उत्पाद में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है और दोनों ही समान वस्तुएं हैं। आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद और संबद्ध देशों से आयातित उत्पाद आवश्यक उत्पाद विशिष्टताओं जैसे भौतिक और रासायनिक विशिष्टताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य एवं उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनीय हैं। उपभोक्ता दोनों का ही परस्पर बदल कर उपयोग कर सकते हैं और करते रहे हैं। दोनों ही तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के तहत उन्हें 'समान वस्तु' के रूप में माना जाना चाहिए। इस प्रकार, वर्तमान जांच की शुरुआत के प्रयोजनों के लिए, आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद को प्रथम दृष्टया संबद्ध देशों से आयात किए जा रहे उत्पाद के समान वस्तु माना गया है।

ग. घरेलू उद्योग और आधार

9. यह आवेदन रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) द्वारा दाखिल किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध उत्पाद के दो उत्पादकों में से एक है। आवेदक का उत्पादन भारत में समान वस्तु के घरेलू उत्पादन में एक बड़ा हिस्सा है। अन्य निर्माता ने भी आवेदन का समर्थन किया है।
10. प्रदान की गई सूचना के आधार पर, यह देखने में आया है कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के तात्पर्य से 'घरेलू उद्योग' होता है और यह आवेदन नियम 5(3) के अनुसार आधार के मानदंडों को पूरा करता है।

घ. संबद्ध देश

11. वर्तमान पाटनरोधी जांच के लिए संबद्ध देश यूरोपीय संघ, जापान, कोरिया गणराज्य, रूस और थाईलैंड हैं।

ङ. जांच की अवधि

12. आवेदक ने जांच की अवधि (12 माह की अवधि) के रूप में दिनांक 1 अक्टूबर 2023 - 30 सितंबर 2024 का प्रस्ताव दिया था। प्राधिकारी ने जांच के प्रयोजन के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तावित अवधि पर विचार किया है। क्षति जांच की अवधि में 2021-22, 2022-23, 2023-24 की अवधि और जांच की अवधि शामिल होगी।

च. कथित पाटन का आधार**i. सामान्य मूल्य**

13. आवेदक ने यूरोपीय संघ में प्रचलित कीमतों के बारे में जानकारी प्रदान की है। आवेदक ने भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ समायोजित किया गया है। आवेदक ने दावा किया है कि उनके पास जापान, कोरिया गणराज्य, रूस और थाईलैंड में बिक्री मूल्य के किसी भी साक्ष्य तक पहुंच नहीं है। इसलिए, आवेदक ने भारत में उत्पादन की लागत के सर्वोत्तम अनुमानों के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया है, जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्यय के साथ उचित लाभ मार्जिन के साथ समायोजित किया गया है।
14. आरंभिक उद्देश्य के लिए, प्राधिकरण ने भारत में उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है।

ii. निर्यात कीमत

15. विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजी सिस्टम डेटा में सूचित किए गए विचाराधीन उत्पाद की सीआईएफ कीमत पर विचार किए जाने के बाद किया गया है। समुद्री माल भाड़ा, समुद्री बीमा, बैंक शुल्क, बंदरगाह व्यय और अंतर्देशीय माल भाड़ा व्यय, द्वितीयक पैकेजिंग, क्रेडिट लागत और वस्तुसूची ले जाने की लागत के लिए समायोजन किए जाने का दावा किया गया है।

iii. पाटन मार्जिन

16. सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत की कारखाना बाह्य स्तर पर तुलना की गई है। इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं का सामान्य मूल्य कारखाना बाह्य निर्यात कीमत से काफी अधिक है, जो *प्रथम दृष्टया* यह दर्शाता है कि संबद्ध देशों से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं को भारतीय बाजार में पाटित किया जा रहा है और पाटन मार्जिन *न्यूनतम* से अधिक है, जिससे जांच शुरू किए जाने का औचित्य सिद्ध होता है। आवेदक ने निष्पक्ष तुलना सुनिश्चित करने के लिए मासिक आधार पर पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन का निर्धारण करने का भी अनुरोध किया है। प्राधिकारी द्वारा सभी हितबद्ध पक्षकारों से टिप्पणियां प्राप्त करने के बाद पाटन और क्षति मार्जिन का मासिक निर्धारण किए जाने की आवश्यकता का परीक्षण किया जाएगा।

छ. क्षति का साक्ष्य और कारणात्मक संबंध

17. घरेलू उद्योग को हुई क्षति का आकलन करने के लिए आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना पर विचार किया गया है। आवेदक ने यह दावा किया है कि उसे वास्तविक क्षति हुई है तथा पाटित किए गए आयातों के परिणामस्वरूप आगे और भी क्षति होने की आशंका है। क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के आयात और आर्थिक मापदंडों के संबंध में सूचना यह दर्शाती है कि क्षति अवधि के दौरान आयातों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है तथा यह भारतीय उत्पादन और खपत के संबंध में महत्वपूर्ण है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती हो रही हैं तथा कीमतों में वृद्धि पर रोक लग रही है, जो अन्यथा होती। इसके परिणामस्वरूप, आवेदक को लाभ में गिरावट, नकदी हानि तथा नियोजित पूंजी पर कम प्रतिफल प्राप्त हुआ है। संबद्ध देशों से पाटित किए गए आयातों से घरेलू उद्योग को हो रही क्षति के पर्याप्त *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य तौजूद हैं, जो पाटनरोधी जांच की शुरुआत को उचित ठहराते हैं।

ज. पाटनरोधी जांच की शुरुआत

18. घरेलू उद्योग द्वारा अथवा उसकी ओर से दाखिल किए गए विधिवत प्रमाणित आवेदन के आधार पर तथा आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए *प्रथम दृष्टया* साक्ष्य के आधार पर, जो संबद्ध देशों के मूल के अथवा वहां से निर्यातित विचाराधीन उत्पाद के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति तथा ऐसे कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध को प्रमाणित करता है, प्राधिकारी स्वयं को संतुष्ट करते हुए तथा नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अनुसार, संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के संबंध में किसी कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए जांच शुरुआत करते हैं, और पाटनरोधी शुल्क की ऐसी राशि की सिफारिश करते हैं, जो यदि लगाई जाती है, तो घरेलू उद्योग को हुई क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगी।

झ. प्रक्रिया

19. वर्तमान जांच के लिए नियमावली के नियम 6 में दिए गए सिद्धांतों का पालन किया जाएगा।

ज. सूचना की प्रस्तुति

20. सभी पत्राचार प्राधिकारी को ईमेल पते adv13-dgtr@gov.in, Consultant-dgtr@nic.in, dd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जाने चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अनुरोध का वर्णनात्मक भाग सर्व योग्य पीडीएफ/ एमएस वर्ड फॉर्मेट में हो और डेटा फाइलें एमएस एक्सेल फॉर्मेट में हों।
21. संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों/ निर्यातकों, भारत में उनके दूतावास के माध्यम से उनकी सरकारों, संबद्ध वस्तुओं से संबंधित भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं और घरेलू उत्पादकों को अलग से सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर निर्धारित प्रारूप और तरीके से सभी संगत सूचना दाखिल कर सकें।
22. कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी जांच के संबंध में अपने अनुरोध निर्धारित समय सीमा के भीतर निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से नीचे उल्लिखित ईमेल पतों पर प्रस्तुत कर सकते हैं।
23. प्राधिकारी के समक्ष कोई गोपनीय अनुरोध करने वाले किसी भी पक्षकार को अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका एक अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराना आवश्यक है।
24. हितबद्ध पक्षकारों को यह भी परामर्श दिया जाता है कि वे इस जांच के संबंध में किसी भी अद्यतन सूचना के लिए प्राधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.dgtr.gov.in/> को नियमित रूप से देखते रहें।

ट. समय सीमा

25. वर्तमान जांच के संबंध में कोई भी सूचना पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (4) के अनुसार सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिनों (30 दिन) के भीतर ईमेल पतों adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dd16-dgtr@gov.in और dd17-dgtr@gov.in पर ईमेल के माध्यम से प्राधिकारी को भेजी जानी चाहिए। तथापि, यह उल्लेखनीय है कि उक्त नियम के स्पष्टीकरण के अनुसार, सूचना और अन्य दस्तावेजों के लिए मांग करने के संबंध में सूचना निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा भेजे जाने अथवा निर्यातक देशों के उपयुक्त राजनयिक प्रतिनिधि को प्रेषित किए जाने की तारीख से एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुई मानी जाएगी। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी पाई जाती है, तो प्राधिकारी नियमों के अनुसार रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।
26. सभी हितबद्ध पक्षकारों को यह परामर्श दिया जाता है कि वे वर्तमान जांच में अपने हित (हित की प्रकृति सहित) से अवगत कराएं और उपरोक्त समय सीमा के भीतर अपने प्रश्नावली उत्तर/ अनुरोध दाखिल करें।
27. जहां कोई हितबद्ध पक्षकार अनुरोध दाखिल किए जाने के लिए अतिरिक्त समय की मांग करता है, तो उसे पाटनरोधी नियमावली, 1995 के नियम 6 (4) के अनुसार ऐसे समय विस्तार के लिए पर्याप्त कारण का प्रदर्शन करना होगा और ऐसा अनुरोध इस अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आना चाहिए।

ठ. गोपनीय आधार पर सूचना की प्रस्तुति

28. जहां वर्तमान जांच में कोई पक्षकार प्राधिकारी के समक्ष गोपनीय अनुरोध करता है अथवा गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करता है, तो ऐसे पक्षकार को नियमावली के नियम 7 (2) के अनुसार और इस संबंध में प्राधिकारी द्वारा जारी संगत व्यापार सूचना के अनुसार ऐसी सूचना का एक अगोपनीय पाठ भी प्रस्तुत करना आवश्यक होता है।
29. ऐसे अनुरोधों के प्रत्येक पृष्ठ के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से 'गोपनीय' अथवा 'अगोपनीय' के रूप में अंकन किया जाना चाहिए। प्राधिकारी को बिना ऐसे अंकन के प्रस्तुत किया गया कोई भी अनुरोध प्राधिकारी द्वारा 'अगोपनीय' सूचना मानी जाएगी और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसे अनुरोधों का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे।
30. गोपनीय पाठ में वह सभी सूचना शामिल होगी जो गोपनीय प्रकृति की है, और/ अथवा ऐसी अन्य सूचना शामिल होगी, जिसके लिए ऐसी सूचना का आपूर्तिकर्ता गोपनीय होने का दावा करता है। ऐसी सूचना के लिए जिसके गोपनीय प्रकृति की बताया जाता है अथवा ऐसी सूचना जिसके बारे में अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा किया गया है, सूचना के आपूर्तिकर्ता को दी गई सूचना के साथ एक उचित कारण का विवरण प्रदान करना आवश्यक है कि ऐसी सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।
31. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दाखिल की गई सूचना का अगोपनीय पाठ गोपनीय पाठ की प्रतिकृति होना चाहिए, जिसमें गोपनीय सूचना को अधिमानतः सूचीबद्ध अथवा खाली रखा जाना चाहिए (जहां सूचीबद्ध करना संभव नहीं है) और ऐसी सूचना को उस सूचना के आधार पर उचित और पर्याप्त रूप से संक्षेप में दिया जाना चाहिए, जिस पर गोपनीयता का दावा किया जाता है।
32. गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना के सारांश को उचित रूप से समझने के लिए अगोपनीय सारांश में पर्याप्त विवरण होना चाहिए। तथापि, असाधारण परिस्थितियों में, गोपनीय सूचना प्रस्तुत करने वाला पक्षकार यह संकेत दे सकता है कि ऐसी सूचना सारांश के लिए अतिसंवेदनशील नहीं है, और नियमावली, 1995 के नियम 7 के संदर्भ में पर्याप्त और उचित स्पष्टीकरण युक्त कारणों का एक विवरण और प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना, कि ऐसा सारांश क्यों संभव नहीं है, प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए प्रदान किया जाना चाहिए।
33. हितबद्ध पक्षकार दस्तावेजों के अगोपनीय पाठ को परिचालित किए जाने की तारीख से 7 दिनों के भीतर गोपनीयता के मामलों पर अपनी टिप्पणियाँ दे सकते हैं।
34. नियमावली के नियम 7 के अनुसार सार्थक अगोपनीय पाठ अथवा पर्याप्त और समुचित कारण के विवरण के बिना किया गया कोई भी अनुरोध तथा गोपनीयता के दावे पर प्राधिकारी द्वारा जारी उचित व्यापार सूचना को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड पर नहीं लिया जाएगा।
35. प्राधिकारी प्रस्तुत की गई सूचना की प्रकृति की जांच किए जाने के बाद गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता के लिए अनुरोध उचित नहीं है अथवा

यदि सूचना का आपूर्तिकर्ता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा सामान्य या सारांश रूप में इसका प्रकटीकरण करने को अधिकृत करने के लिए तैयार नहीं है, तो वह ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।

36. प्राधिकारी, प्रदान की गई सूचना की गोपनीयता की आवश्यकता से संतुष्ट होने तथा उसे स्वीकार किए जाने के बाद, ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की विशिष्ट अनुमति के बिना किसी भी पक्षकार को इसका प्रकटन नहीं करेंगे।

ड. सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

37. पंजीकृत हितबद्ध पक्षकारों की सूची डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी, जिसके साथ ही उन सभी से अनुरोध किया जाएगा कि वे अपने अनुरोधों के अगोपनीय पाठ को सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ईमेल करें।

ढ. असहयोग

38. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार समुचित अवधि के भीतर अथवा प्राधिकारी द्वारा इस जांच शुरुआत अधिसूचना में निर्धारित समय के भीतर आवश्यक सूचना तक पहुंच से इनकार करता है अथवा अन्यथा प्रदान नहीं करता है, अथवा जांच में महत्वपूर्ण रूप से बाधा डालता है, तो प्राधिकारी ऐसे हितबद्ध पक्षकार को असहयोगी घोषित कर सकते हैं और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केंद्र सरकार को ऐसी यथाउपयुक्त सिफारिशें कर सकते हैं।

दर्पण जैन, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 29th March, 2025

Case No – AD(OI) - 07/2025

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series from European Union, Japan, Korea RP, Russia and Thailand.

F. No. No. 6/07/2025-DGTR.—Having regards to the Customs Tariff Act 1975, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 thereof, as amended from time to time (hereinafter also referred to as the “Rules or AD Rules”), Reliance Industries Limited (hereinafter referred to as the “applicant” or the “Petitioner”) has filed an application before the Designated Authority (hereinafter referred to as the “Authority”) for initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Emulsion Styrene Butadiene Rubber” (hereinafter referred to as the “subject goods” or “product under consideration” or “ESBR” from European Union, Japan, Korea RP, Russia and Thailand (“subject countries”).

2. The applicant has alleged that material injury and threat of material injury is being caused due to the dumped imports of the subject goods from the subject countries and has requested for the imposition of anti-dumping duties on the imports of the subject goods, originating in or exported from the subject countries.

A. Product under Consideration

3. The product under consideration is Emulsion Styrene Butadiene Rubber of 1500 series, abbreviated as ESBR -1500.
4. A number of grades of SBR are produced, which are characterised by the level of copolymer (% of styrene), emulsifier type, nominal mooney viscosity, coagulation, specific gravity and product stain. They are segregated into series 1000, 1500, 1600, 1700, 1800 and 1900. The product under consideration is ESBR 1500 series only.
5. The subject goods are mainly used to manufacture tyres as it has good abrasion resistance and good aging stability when protected by additives. It is also used in conveyer belts, shoe soles, v-belts, moulded rubber goods etc. In comparison to natural rubber, ESBR has better process ability, homogeneity, heat aging and abrasion resistance.
6. The product under consideration is classified under Chapter 40, under tariff code 4002 19. The customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the present investigation.
7. No PCN methodology has been proposed by the applicant. However, the interested parties in the subject investigation may provide their comments on the PUC/PCN methodology, if any, within 15 days from the date of initiation of this investigation.

B. Like article.

8. The applicant has submitted that there are no significant differences in the product produced by the applicant and those exported from the subject countries, and both are like articles. The product produced by the applicant and those imported from the subject countries are comparable in terms of essential product characteristics such as physical and chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & usage, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. Consumers can use and have been using the two interchangeably. The two are technically and commercially substitutable, and hence, should be treated as 'like article' under the Rules. Thus, for the purposes of initiation of the present investigation, the product produced by the applicant has been *prima facie* considered as like article to the product being imported from the subject countries.

C. Domestic industry and standing.

9. The application has been filed by Reliance Industries Limited (RIL). The applicant is one of the two producers of the subject product in India. The production of the applicant accounts for a major proportion in the domestic production of the like article in India. The other producer has also supported the application.
10. Based on the information provided, it is seen that the applicant constitutes 'domestic industry' within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

D. Subject countries

11. The subject countries for the present anti-dumping investigation are European Union, Japan, Korea RP, Russia and Thailand.

E. Period of investigation

12. The applicant had proposed 1st October 2023 – 30th September 2024 as the period of investigation (period of 12 months). The Authority has considered the period proposed by the applicant for the purpose of the investigation. The injury investigation period will cover the period of 2021-22, 2022-23, 2023-24 and the period of investigation.

F. Basis of alleged dumping**i. Normal value**

13. The applicant has provided information on the prevailing prices in European Union. The applicant has additionally determined the normal value based on the best estimates of cost of production in India duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin. The applicant has claimed that they do not have access to any evidence of selling price in Japan, Korea RP, Russia and Thailand. Therefore, applicant has determined the normal value based on the best estimates of cost of production in India duly adjusted with selling, general and administrative expenses, along with a reasonable profit margin.
14. For the purpose of initiation, the Authority has considered normal value based on cost of production in India.

ii. Export price

15. The export price of the product under consideration has been determined by considering the CIF price of the product under consideration as reported in DG Systems data. Adjustments have been claimed for ocean freight, marine insurance, bank charges, port expenses and inland freight expenses, secondary packaging, credit costs and inventory carrying costs.

iii. Dumping margin

16. The normal value and export price have been compared at the ex-factory level. There is sufficient evidence that the normal value of the subject goods in the subject countries is significantly higher than the ex-factory export price indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries into the Indian market and the dumping margin is above *de-minimis* so as to justify the initiation of the investigation. The applicant has also requested for dumping margin and injury margin be determined on a monthly basis to ensure a fair comparison. The Authority will examine the need for a monthly determination of dumping and injury margin after receiving comments from all interested parties.

G. Evidence of injury and causal Link

17. Information furnished by the applicant has been considered for assessment of injury to the domestic industry. The applicant has claimed that it has suffered material injury and there is a threat of further injury as a result of the dumped imports. The information concerning imports and economic parameters of the domestic industry over the injury period show that the imports have increased in absolute terms over the injury period and are significant in relation to the Indian production and consumption. The imports are undercutting the prices of the domestic industry and have prevented price increases, which otherwise would have occurred. As a result, the applicant witnessed decline in profits, cash losses and a low return on its capital employed. There is sufficient *prima facie* evidence of injury being caused to the domestic industry by the dumped imports from the subject countries to justify the initiation of an anti-dumping investigation.

H. Initiation of anti-dumping investigation

18. On the basis of the duly substantiated application filed by or on behalf of the domestic industry, and having satisfied itself, on the basis of the *prima facie* evidence submitted by the applicant, substantiating dumping of the product under consideration originating in or exported from the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between such alleged dumping and injury, and in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules, the Authority, hereby, initiates an investigation to determine the existence, degree and effect of any alleged dumping in respect of the subject goods originating in or exported from the subject countries and to recommend the amount of anti-dumping duty, which is levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

I. Procedure

19. Principles, as given in Rule 6 of the Rules, will be followed for the present investigation.

J. Submission of information

20. All communication should be sent to the Authority via email at the email addresses adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@nic.in, dd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in. It should be ensured that the narrative part of the submission is in searchable PDF/ MS Word format and data files are in MS Excel format.
21. The known producers/ exporters from the subject countries, their Governments through their Embassy in India, the importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic producer are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below.
22. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below on the email addresses mentioned hereinabove.
23. Any party making any confidential submission before the Authority is required to make a non-confidential version of the same available to the other interested parties.
24. Interested parties are further advised to keep a regular watch on the official website of the Authority <https://www.dgtr.gov.in/> for any updated information with respect to this investigation.

K. Time limit

25. Any information relating to the present investigation should be sent to the Authority via email at the email addresses adv13-dgtr@gov.in, consultant-dgtr@govcontractor.in, dd16-dgtr@gov.in and dd17-dgtr@gov.in within thirty days (30 days) from the date of receipt of the notice as per Rule 6(4) of the Anti-Dumping Rules. It may, however, be noted that in terms of explanation of the said Rule, the notice calling for information and other documents shall be deemed to have been received within one week from the date on which it was sent by the Designated Authority or transmitted to the appropriate diplomatic representative of the exporting countries. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its finding on the basis of the facts available on records in accordance with the Rules.
26. All the interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant investigation and file their questionnaire response/ submissions within the above time limit.
27. Where an interested party seeks additional time for filing of submissions, it must demonstrate sufficient cause for such extension in terms of Rule 6(4) of the AD Rules, 1995 and such request must come within the time stipulated in this notification.

L. Submission of information on a confidential basis

28. Where any party to the present investigation makes confidential submissions or provides information on a confidential basis before the Authority, such party is required to simultaneously submit a non-confidential version of such information in terms of Rule 7(2) of the Rules and in accordance with the relevant trade notices issued by the Authority in this regard.
29. Such submissions must be clearly marked as 'confidential' or 'non-confidential' at the top of each page. Any submission that has been made to the Authority without such markings shall be treated as 'non-confidential' information by the Authority, and the Authority shall be at liberty to allow other interested parties to inspect such submissions.

30. The confidential version shall contain all information which is, by nature, confidential, and/or other information, which the supplier of such information claims as confidential. For the information which is claimed to be confidential by nature, or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.
31. The non-confidential version of the information filed by the interested parties should be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (where indexation is not possible) and such information must be appropriately and adequately summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed.
32. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on a confidential basis. However, in exceptional circumstances, the party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons containing a sufficient and adequate explanation in terms of Rule 7 of the Rules, 1995, and appropriate trade notices issued by the Authority, as to why such summarization is not possible, must be provided to the satisfaction of the Authority.
33. The interested parties can offer their comments on the issues of confidentiality within 7 days from the date of circulation of the non-confidential version of the documents.
34. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or a sufficient and adequate cause statement in terms of Rule 7 of the Rules, and appropriate trade notices issued by the Authority, on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.
35. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.
36. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorisation of the party providing such information.

M. Inspection of public file

37. A list of registered interested parties will be uploaded on the DGTR's website along with the request therein to all of them to email the non-confidential version of their submissions to all other interested parties.

N. Non-cooperation

38. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or within the time stipulated by the Authority in this initiation notification, or significantly impedes the investigation, the Authority may declare such interested party as non-cooperative and record its findings based on the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit.

DARPAN JAIN, Designated Authority